Item No. 08 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 709/2023
(IA No. 272/2024)

Lal Ji Kumar Applicant

Versus

Divisional Forest Officer-Nainital Respondent

Date of hearing: 23.09.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

Respondent: Mr. Deepak Bora and Ms. Saima Khatoon , Advocates for State of Uttarakhand with Ms. Kahkashan Naseem, Additional Secretary Environment and Mr. C S Joshi DFO
Mr. Balendu Shekhar and Ms. Tanisha Samanta, Advocates with Mr Neeraj Kumar, Officer, Director, UKGD Survey of India and Mohd. Fareed, Officer Surveyor.
Mr. Mukesh Verma and Ms. Vatsala Tripathi, Advocates for UKPCB (through VC)
Respondent No. 7 in Person.

ORDER

1. Mr. Lal Ji Kumar has filed present application under the provisions of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010'**) for issue of directions to the concerned authorities to demarcate boundary line between Revenue and Forest land precisely and scientifically, by establishing boundary pillars with precise geo coordinates according to the approved/notified Revenue Maps, remove encroachments on forest land and take possession of the same.

2. Applicant has stated that Gethiya, a small Revenue village having area approximately 5 to 7 hectares is located on a hill top in Nainital, Uttarakhand. It is surrounded on all its side by the Reserved Forest. Some unknown persons have dismantled boundary pillars demarcating

boundary lines between forest land and revenue land and made encroachments over forest land including Khasra numbers 421, 423 and 424. Complaints were made to the concerned authorities but no action has been taken.

3. Complaint was registered on 28.11.2023 and Tribunal found it appropriate to issue notices to respondents impleaded in Original Application (hereinafter referred to as **'OA'**) i.e. Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division, District Magistrate, Nainital and Commissioner/Secretary Board of Revenue, Uttarakhand. Tribunal also found it appropriate to obtain a factual report for which it constituted a Joint Committee comprising representative of Uttarakhand Pollution Control Board (hereinafter referred to as **'UKPCB'**); Divisional Forest Officer, Nainital (hereinafter referred to as **'DFO, Nainital'**); and District Magistrate, Nainital (hereinafter referred to as **'DM, Nainital'**).

4. Committee was required to submit report within 2 months.

5. Joint Committee report was submitted through UK PCB which stated as under:-

> *"2- राजस्व अभिलेखों के अनुसार ग्राम गेठिया पट्टी भवाली के खसरा नम्बर 397, 421, 423, 424 की खतौनी के अवलोकन से खसरा नम्बर 397 रकदा 0307 है., 421 रकबा 0.135 है., 423 रकबा 0.129 है. कुल 03 खसरा नम्बरी का रकबा 0.571 हेक्टेयर वर्तमान समय में नॉन ज्येड०ए० खतौनी खाता संख्या 70 में सरकार उत्तराखण्ड श्रेणी 09(3)3 वंजर के रूप में दर्ज अभिलेख है जो मौके पर मंजर स्थिति में ही है जो कि वास्तविक स्वरूप में है। जिन पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होना नही पाया गया। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान वन विभाग के द्वारा भी खसरा नम्बरों 397, 421, 423 को अपने क्षेत्र से बाहर होना बताया गया है। परन्तु खसरा संख्या 424 में वन विभाग के द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत होना बताया गया जबकि राजस्व विभाग के अनुसार खसरा नम्बर 424 रकया 1.097 हेक्टेयर श्रेणी 01 (क) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधरों के*

अधिकार में हंसा दत्त आदि खातेदारों के नाम पर दर्ज है। हाल बन्दोबस्ती नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 424 की सीमा यन विभाग की सीमा से मिलान करती है जिसमे वन विभाग के पिलर संख्या 08 व 09 खसरा नम्बर 424 के बाहर स्थित है।

2- वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग के नक्शे के अनुसार खसरा नम्वर 424 मनोरा रेंज अन्तर्गत कुरिया कम्पार्ट संख्या 05 के अन्तर्गत आ रहा है। इसके अतिरिक्त उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 197/13-1 दिनांक 15.01.2024 से अवगत कराया है कि पूर्व में भी इस भूमि के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल के द्वारा अपने पत्र संख्या 2554/27-19 दिनांक 28.01.2021 से सर्वेक्षण का कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग से कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संनमक-क)

3- वन विभाग के द्वारा खसरा संख्या 424 में सीमा विवाद के संबंध में सर्वे हेतु दिनांक 24.01.2024 की तिथि नियत की गयी थी। जिसमें सर्वेयर के द्वारा भी अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग की खतौनी में दर्ज खसरा संख्या 424 वास्तविक रूप से आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है जो कि वन विभाग के कुरिया ब्लॉक कक्ष संख्या 05 के नाम से गजट नोटिफिकेशन वर्ष 1933 में दर्ज है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है। (संनानक-(1))

4- राजस्य विभाग के अनुसार खत्तरा नम्बर 424 की पैमाईश करने पर हाल बन्दोबस्ती नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 424 को गीगा सही होनी पायी गयी जिसका खातेदार राजेन्द्र नाथ साह द्वारा 0.252 हेक्टेयर भूमि विक्रय पत्र के द्वारा मनोज सिंह नेगी पुत्र एम०एस० नेगी को विक्रय की गयी है जिसका दा०खा० खतौनी में अमलदरामद है। खसरा नम्बर 224 मौके पर पंजार है जिस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। खतौनी नफल संतान है। (सेलमल-ख)

5- हाल बन्दोवस्ती खसरा नम्बर 424 की सीमा वन विभाग की सीमा से मिलती है जिसके सम्यन्ध में हाल बन्दोबस्ती राजत्य नरों के अनुसार भोकै पर सीमांकन करने से खसरा नम्बर 424 के खातेदारों द्वारा बन विभाग की सीमा पर कोई अतिक्रमण होना नहीं पाया गया। हाल बन्दोबस्त नो की प्रति संलग्न है। (खेलानक-ग)

6- वन विभाग के द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान अवगत कराया है कि उक्त खतरा नम्बर 424 की भूमि वन विभाग के सीमा के अन्तर्गत आ रही है तथा यह क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र में आता है। अतः वस्तुस्थिति को स्पष्ट करने हेतु साबिक व हाल बन्दोवस्त के रिकार्ड को जिला कार्यालय के मात अभिलेखागार से तलब किया गया तथा तहसीलदार नैनीताल को इस संबंध में आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु अवगत कराया गया है।

7- तहसीलदार नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या 318/र.का./2024 दिनांक 01 फरवरी 2024 के द्वारा आख्या प्रेषित की गयी, जिसके मुख्य विन्दु निम्नवत् है-

- साबिक बन्दोबस्त के मौजा वेलुवाखान (हाल ग्राम गैठिया) चक केमुआतल्ला पट्टी छ खाता परगना छ खाता जिला नैनीताल के हाल खसरा नम्बर 424 को साफ खसरा से मिलान करने पर साविक खसरा नम्बर 816 जिसका रकबा 54 नाली 11 मुट्ठी पाया गया। परन्तु वह साबिक खसरा नम्बर साचिक नक्शे में 172/915 के तौर पर अंकित होना पाया गया। यह साबिक नक्शा वर्ष 1899-97 के बन्दोवस्त के दौरान तैयार किया गया था।
- उपरोका नलों में वन विभाग की पिलर संख्या 02 एवं 01 राजस्व नवशे के अन्दर है तथा पिलर संख्या 03, 04, 05, 07, 08 राजस्व नश्शे को सीमा से लगे हुए है। साबिक बन्दोबस्त के नक्शे की सत्यापित प्रति संलग्न है। (सेलान-ब)
- उपरोक्त साविक नगो के आधार पर ही वर्तमान बन्दोबस्ती नवशे को तैयार किया गया है। जो कि वर्ष 1965-55 ने तैयार किया गया है। इस आधार पर वन विभाग के पिलर संख्या 02, 03 को वर्तमान हाल बन्दोवस्ती नक्शे से हटा दिया गया है। वहीं यह भी दृष्टिगोयर हो रहा है कि वर्ष 1899-97 के बन्दोबस्त में से ही उक्त दोनों पिलर नक्शों में राजस्व विभाग के खसरा संख्या 172/916 के अन्दर आच्छादित थे।
- तहसीलदार नैनीताल के द्वारा अपनी आख्या में निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट किया है कि वर्ष 1899-97 के बन्दोबस्त के दौरान से ही हाल खसरा संख्या 424 (साविक खसरा नम्बर 172/916) का रकबा 1.097 है. ही है तथा पन विभाग का आंशिक क्षेत्र पूर्व से ही राजस्व नक्शे में आच्छादित चला आ रहा था जिसे हाल गन्दोवसा 1955-56 के दौरान नक्शे से हटा दिया गया है। हाल गन्दोवस्त नक्शे में कोई भी पिलर राजस्व विभाग के नवशे की सीमा के अन्तर्गत प्रदर्शित नहीं है। (सेलानक-च) उका तथ्यों से

स्पष्ट है कि राजस्व विभाग एवं वन विभाग के मध्य राजस्य विभाग के ग्राम गेठिया के खाता खतौनी संख्या 144 के खसरा संख्या 424 एवं वन विभाग के कुरिया ब्लॉक के कम्पार्ट संख्या 05 में नक्शे को लेकर विवाद की स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है।

उक्त के संबंध में उत्तराखण्ड शासन के राजस्य अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 09.10.2023 के द्वारा दन एवं राजस्व विभाग के मध्य भूमि के रिकार्ड एवं नियमों आदि में मत भिन्नता के संबंध में दिनांक 11. 09.2023 को आहुत वैठक में इस प्रकार के प्रकरणों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस समिति में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं चन बन्दोवस्त अधिकारी सदस्य के तौर पर सम्मिलित है। अतः विषयगत प्रकरण को संबंधित स्थायी समिति को संदर्भित किया जाना उचित प्रतीत होता है।"

Translation by Tribunal

"2- According to the revenue records, from the observation of Khatauni of Khasra No. 397, 421, 423, 424 of Village Gethiya Patti Bhawali, Khasra No. 397 area is 0.307, 421 area is 0.135, 423 area is 0.129. Total area of 03 Khasra nos. is 0.571 hectare. At present, in Non-ZA Khatauni Account No. 70, Government of Uttarakhand Category 09(3)3 is recorded as barren, which is in the barren condition on the spot and in its actual form. No encroachment of any kind was found on that place. During the joint survey, the Forest Department also declared Khasra nos. 397, 421, 423 to be outside its area. But Khasra no. 424 was declared within its limit by the Forest Department, whereas according to the Revenue Department, Khasra no. 424 area 1.097 hectare is registered in the name of account holders like Hansa Dutt etc. under the rights of landholders with category 01 (a) transferable rights. According to the recent settlement map, the boundary of Khasra no. 424 matches with the boundary of the Forest Department, in which pillar numbers 08 and 09 of the Forest Department are located outside Khasra no. 424.

2– The Forest Department has informed that according to the map of the Department, Khasra no. 424 is coming under Kuria Compartment no. 05 under Manora Range. Apart from this, the Deputy Divisional Forest Officer, Nainital, Forest Division, Nainital has informed vide letter number 197/13–1 dated 15. 01. 2024 that earlier a dispute had also arisen regarding this land, in which the Divisional Forest Officer, Nainital Forest Division, Nainital had sent a letter no. 2554/27–19 dated 28. 01. 2021 to get the survey work done by the Indian Survey Department. A copy of the letter is attached. (Annexure-A)

3- The date i.e. 24. 01. 2024 was fixed by the Forest Department for the survey regarding the border dispute in Khasra no. 424. In which the surveyor also informed that Khasra no. 424 recorded in the Khatauni of the Revenue Department is actually within the boundary of the reserved forest area which is recorded in the gazette notification of the year 1933 in the name of Kuria Block Room No. 05 of the Forest Department. A copy of the survey report is attached. (Annexure-(1))

4- According to the Revenue Department, on measuring Khattra No. 424, as per the current settlement map, Khasra No. 424 was found to be correct as Giga, whose account holder Rajendra Nath Sah has sold 0.252 hectare of land through a sale deed to Manoj Singh Negi S/o MS Negi, whose claim is recorded in the Khatauni. Khasra No. 224 is a barren the spot, on which there is no encroachment of any kind. Khatauni is Nafal Santan. (Annexure-B)

5- The boundary of the current settlement Khasra no. 424 meets the boundary of the Forest Department, in respect of which, after demarcation on the spot as per the current settlement revenue rates, no encroachment was found on the boundary of the Forest Department by the account holders of Khasra no. 424. A copy of the current settlement number is enclosed. (Annexure-C)

6- During the joint survey, the Forest Department has informed that the land of Khasra No. 424 falls under the boundary of the Forest Department and this area falls in the reserved forest area. Therefore, to clarify the actual situation, the records of the past and recent settlement were summoned from the archives of the District Office and the Tehsildar Nainital has been informed to submit a report in this regard.

7- The Tehsildar Nainital sent a report vide letter number 318/2. Ka./2024 dated 01 February 2024, the important points are as follows-

- *On matching the current Khasra no. 424 of Mauja Veluwakhan (present village Gaithia) Chak Kemuatalla Patti Chha Khata Pargana Chha Khata District Nainital of the previous settlement with the clean Khasra, the real Khasra no. 816 whose area is 54 Naali 11 fist was found. But real Khasra no. was found to be marked as 172/915 in the actual map. This real map was prepared during the settlement of the year 1899-97.*

- *In the above mentioned maps, pillar number 02 and 01 of the forest department are within the revenue map and pillar number 03, 04, 05, 07, 08 are adjacent to the revenue map boundary. A*

certified copy of the map of the previous settlement is attached. (Annexure-B)

- *The present settlement map has been prepared on the basis of the above mentioned old maps which was prepared in the year 1965–55. On that basis, pillar nos. 02, 03 of the forest department have been removed from the present settlement map. It is also visible that in the settlement map of the year 1899–97, the above two pillars were covered under Khasra no. 172/916 of the Revenue Department.*

- *In his report, Tehsildar Nainital has clarified in conclusion that the area of the current Khasra no. 424 (Former Khasra number 172/916) is 1.097 hectares since the settlement of 1899-97 and a part of the area of the Forest Department was already covered in the revenue map, which has been removed from the map during the recent Gandovasa 1955-56. In the recent settlement map, no pillar is shown within the boundary of the Revenue Department's map. (Annexure-E) It is clear from these facts that a situation of dispute is visible between the Revenue Department and the Forest Department regarding the map of Khasra no. 424 of Khata Khatauni no. 144 of Village Gethiya of the Revenue Department and Compartment no. 05 of Kuria Block of the Forest Department.*

In the above reference, vide letter dated 09.10.2023 of Revenue Section-2 of Uttarakhand Government, in the meeting convened on 11.09.2023 regarding the difference of opinion between the Forest Department and Revenue Department in the records and rules of land, etc., instructions have been given to constitute a committee under the chairmanship of the District Magistrate to settle such cases. The concerned Divisional Forest Officer and Forest Settlement Officer are included as members in this committee. Therefore, it seems appropriate to refer the subject matter to the concerned Standing Committee."

6. Report was considered by Tribunal on 15.02.2024. It observed that there was dispute between Revenue Department and Forest Department in respect of land comprising Khata Khatauni No. 144, Khasra No. 424 situated at Village Gethiya and Forest department map of compartment no. 5, Koria Block. Tribunal also noted that for resolution of above dispute, District Level Committee was constituted under the Chairmanship of District Magistrate.

7. DM, Nainital also submitted its reply dated 14.02.2024 wherein observations made in Joint Committee Report were reiterated.

8. Accordingly, Tribunal found it appropriate to implead State of Uttarakhand through Chief Secretary, Government of Uttarakhand; Principal Secretary, Revenue Department, Uttarakhand; and Surveyor General of India as respondents 4 to 5 and notices were issued to them.

9. **IA No. 272/2024** was filed by Manoj Singh Negi seeking his impleadment and he was impleaded as respondent 7.

10. Respondent 5 submitted response dated 11.07.2024 taking stand as under:-

> *"1- मूल आवेदन संख्या-709/2023 'लाल जी कुमार बनाम् डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर-नैनीताल, फॉरेस्ट डिविजन व अन्य में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2024 के अनुपालन हेतु शासन के पत्र सं0-1/192466/2024 दिनांक 21. 02.2024 एवं पत्र सं0-1/201861/2024 दिनांक 26.03.2024 के द्वारा ग्राम गेठिया, जनपद नैनीताल स्थित प्रश्नगत भूमि खतौनी खाता सं0-144 खसरा नं0 424, जिसमें राजस्व विभाग एवं वन विभाग के मध्य विवाद है, से संबंधित सभी सुसंगत राजस्व अभिलेखों, मानचित्र आदि सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, नैनीताल को निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी, नैनीताल के पत्र संख्या-02 (09)/12-ज्येड०ए०सी०/2020-21 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 के द्वारा उपजिलाधिकारी सदर, नैनीताल के पत्र दिनांक 01.04.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या मय संलग्नकों सहित शासन को प्रेषित की गयी, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि मौजा बेलुवाखान चक के मुआतल्ला, पट्टी छः खाता, जिला नैनीताल पैमाना 66 ईंच 1 मील वर्ष 1899-97 के सजरे से ग्राम बेलवाखान चक गेठिया, पट्टी छः खाता, तहसील व जिला नैनीताल पैमाना 64 ईंच = 1 मील वर्ष 1955-56 कृषि वर्ष 1363 (वर्तमान ग्राम गेठिया) के सजरे से अन्तर का अवलोकन किया गया। वर्ष 1899-97 के सज़रे में स्थित खसरा सं० 172/926 में फॉरेस्ट पीलर क्रमशः 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 के बीच स्थित राजस्व भूमि की सज़रे में पैमाना अनुसार नाप-जोख की गयी, जो कि माप करने*

पर 0.281 है0 (14 नाली 01 मुट्ठी) अन्तर पायी गयी है, जिसे वर्ष 1899-97 में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है।"

2- ग्राम गेठिया, पट्टी भवाली स्थित प्रश्नगत भूमि के संबंध में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण आख्या (दिनांक रहित) के अनुसार, वर्ष 1899-97 के बन्दोबस्त के दौरान से ही हाल खसरा संख्या-424 (साबिक खसरा नं0 172/916) का रकबा 1.097 है० है तथा वन विभाग का आंशिक क्षेत्र पूर्व से ही राजस्व नक्शे में आच्छादित चला आ रहा था, जिसे हाल बन्दोबस्त 1955-56 के दौरान नक्शे से हटा दिया गया है। हाल बन्दोबस्त नक्शे में कोई भी पिलर राजस्व विभाग के नक्शे की सीमा के अन्तर्गत प्रदर्शित नहीं है। इस प्रकार राजस्व विभाग एवं वन विभाग के मध्य ग्राम गेठिया के खाता खतौनी संख्या 144 के खसरा नं0 424 एवं वन विभाग के कुरिया ब्लॉक के कम्पार्ट संख्या 05 में नक्शे को लेकर विवाद की स्थिति दृष्टिगोचर है। उल्लेखनीय है कि वन विभाग के पास उपलब्ध भूमि के नक्शे एवं जिल्द बन्दोबस्त में रिकार्ड में भिन्नता के कारण राज्य में कतिपय स्थानों पर विवाद की स्थिति है।

3- अतः वन एवं राजस्व विभाग के मध्य भूमि के रिकार्ड एवं नियमों आदि में मत भिन्नता के दृष्टिगत मा० मंत्रीमण्डल के निर्णयोपरान्त इस सम्बन्ध में विस्तृत परीक्षण हेतु राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/125141/2023, दिनांक 26.05.2023 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है। उक्त समिति की दिनांक 11.09.2023 को आहूत बैठक में लिए गये निर्णयोपरान्त जनपद स्तर पर राजस्व एवं वन विभाग के मध्य विवादों के निबटान हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गयी है, जिसमें सम्बन्धित जनपद के डी०एफ०ओ० एवं वन बन्दोबस्त अधिकारी सदस्य हैं तथा उक्त समिति को अधिकृत किया गया है कि वह जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व को आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति में सम्मिलित कर सकेगी। इस प्रकार जिलाधिकारी अपने जनपद के भीतर case by case इस प्रकार के प्रकरणों के परीक्षण हेतु अधिकृत हैं। किसी प्रकरण विशेष के निस्तारण यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो जनपद स्तर पर परीक्षणोंपरान्त ही ऐसे प्रकरणों राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।

4- उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जियोरेफरेंसिंग एवं जी०आई०एस० आधारित Precise survey of identified boundary and creation and maintenance of an enterprise class web/cloud GIS

based forest land decision support system के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.03. 2024 को सम्पन्न बैठक के क्रम में वन विभाग द्वारा SOP भी तैयार की जा रही है, जो राजस्व विभाग एवं वन विभाग की भूमि के चिह्नीकरण में सहायक सिद्ध होगा।"

Tribunal's Translation

"1- In compliance of the order dated 15.02.2024 passed by the Hon'ble Tribunal in the OA No.-709/2023 Lal Ji Kumar Versus Divisional Forest Officer, Nainital, Forest Division &; Ors., the District Magistrate, Nainital was directed to provide a report to the government along with all the relevant revenue records, maps etc. related to the land Khatauni Account No.-144 Khasra No. 424 in question, situated in village Gethiya, District Nainital, in which there is a dispute between the Revenue Department and the Forest Department, vide letter no. 1/192466/2024 dated 21.02.2024 and letter no. 1/201861/2024 dated 26.03.2024. In continuation of the above, the letter no.-02 (09)/12-ZAC/2020-21 dated 2 nd April, 2024 of the District Magistrate, Nainital, the report provided vide letter dated 01.04.2024 of the Sub-Divisional Magistrate Sadar, Nainital was sent to the Government along with attachments, in which it has been informed that the difference was observed from the map of village Belwakhan Chak Gethiya, Patti Six Khata, Tehsil and District Nainital scale 64 inches = 1 mile year 1955-56 agricultural year 1363 (present village Gethiya) with the map of Muatalla, Patti Six Khata, District Nainital scale 66 inches 1 mile year 1899-97 of Mauza Beluwakhan Chak. In the survey of the year 1899-97, the revenue land situated between the forest pillars 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 in Khasra No. 172/926 was measured according to the scale in the survey. On measuring, a difference of 0.281 hectare (14 naali 01 fist) was found, which has been shown in red color in the year 1899-97."

2- According to the joint inspection report (undated) made by the Forest Department and Revenue Department officials regarding the land in question situated in Village Gethiya, Patti Bhawali, the area of the current Khasra no.-424 (former Khasra no. 172/916) since th settlement of the year 1899-97 is 1.097 hectares and a partial area of the Forest Department was already covered in the revenue map, which has been removed from the map during the recent settlement of 1955-56. In the recent settlement map, no pillar is shown within the boundary of the Revenue Department map. Thus, a situation of dispute is visible between the Revenue Department and the Forest Department regarding the map in Khasra No. 424 of Khata Khatauni No. 144 of Village Gethiya and Compartment No. 05 of Kuria Block of the Forest Department. It is worth mentioning that due to the difference in the map of the land available with the Forest

Department and the records in the settlement, there is a situation of dispute at some places in the state.

3- Therefore, in view of the difference of opinion between the Forest and Revenue Department in the land records and rules etc., after the decision of the Hon'ble Cabinet, a high-level committee has been constituted under the chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand Government vide OM No. 1/125141/2023, dated 26.05.2023 of Revenue Section-2, Uttarakhand Government for detailed examination in this regard. After the decisions taken in the meeting of the said committee convened on 11.09.2023, a standing committee has been constituted under the chairmanship of the District Magistrate to settle the disputes between the Revenue and Forest Department at the district level, in which the DFO and Forest Settlement Officer of the concerned district are members and the said committee has been authorized to include the District Government Advocate, Revenue as a special invitee member in the committee as per the requirement. Thus, the District Magistrate is authorized to examine such cases, case by case within his district. If any difficulty arises in resolving a particular case, then such cases will have to be presented before the State Level Committee only after examination at the district level.

4- Apart from the above, it is also to be informed that in relation to Geo-referencing and GIS based Precise survey of identified boundary and creation and maintenance of an enterprise class web/cloud GIS based forest land decision support system, in the sequence of the meeting held on 19.03.2024 under the chairmanship of Chief Secretary, Uttarakhand Government, SOP is also being prepared by the Forest Department, which will prove helpful in the identification of land of Revenue Department and Forest Department."

11. DFO, Nainital also filed its counter affidavit dated 18.07.2024 wherein several provisions of Indian Forest Act, 1927 as amended in State of U.P, from time to time, are referred. In para 34, it is said that there is a dispute between boundaries of Kuria Block. Under instructions of DFO, Nainital vide letter dated 23.01.2024, a team of 03 Surveyors namely; Mr. Ajay Kumar, Surveyor, Almora Forest Division, Almora, Mrs. Neelam Kohli, Surveyor, Nainital Forest Division, Nainital and Mrs, Sunita, Surveyor, Tarai East Forest Division, Haldwani was constituted to inspect land in question and submit report. As per their report, Revenue

Maps show Boundary Pillar No. 07 and 08 of Kuriya Block as Revenue land.

12. Surveyor team further reported that Khasra No. 424 of Village Gethiya, Patti Bhowali, District Nainital in Revenue records, though revenue land but that revenue land is overriding land located in Reserve Forest, Kuria Block.

13. In the circumstances, Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand vide letter dated 13.05.2024 directed survey and demarcation of land through Survey of India.

14. Now Survey of India has submitted its compliance report dated 21.09.2024, annexing annexure R-1 as survey report, which reads as under:-

*"**सर्वेक्षण रिपोर्ट***

1. *मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, मूल आवेदन संख्या-709/2022 लाल जी कुमार बनाम प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल व अन्य के सम्बन्ध में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निदेशालय UKGD ने दिनाँक 01-08-2024 को पत्रांक सं० 1439/17-A-5(L) दिनाँक 29-07-2024 के माध्यम से बैठक आहूत की गई थी परन्तु वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा पत्रांक सं०-99/देहरादून दिनाँक 01-08-2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि नैनीताल में अति वृष्टि होने के कारण बैठक में प्रतिभाग करने में असमर्थता है अतः पुनः दिनाँक 02-08-2024 (पत्र सं० 1470/17-A-5(L) दिनाँक 01-08-2024) को बैठक आहूत की गई जिसमें **मात्र वन प्रभाग, नैनीताल ने प्रतिभाग किया तथा राजस्व विभाग के किसी प्रतिनिधि ने बैठक में प्रतिभाग नहीं किया।***

2. वन प्रभाग, नैनीताल के साथ विचार विमर्श एवं अभिलेखों के अध्ययन के उपरान्त विवादित स्थल को GPS observation द्वारा सर्वे करने का निर्णय किया गया। साथ ही विवादित स्थल का वन प्रभाग, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करवाये गये मानचित्र (Scale 1:15,00) को भारतीय सर्वेक्षण विभाग की

OSM Sheet No. 530/7 पर Super Impose करके स्थित की वास्तविकता जानने की कोशिश की।

3. भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय के पत्र सं० 1212/1147-Project (General)/2070 दिनाँक 01-08-2024 के अनुपालन में विवादित स्थल के GPS सर्वे हेतु श्री मोहम्मद फरीद, अधिकारी सर्वेक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा इस टीम ने दिनाँक 28-08-2024 से दिनाँक 02-09-2024 तक सर्वेक्षण का कार्य किया। GPS सर्वे की रिपोर्ट निम्न प्रकार है-

(i) GPS सर्वेक्षण से प्राप्त निर्देशको को Plot करने पर यह ज्ञात हुआ कि स्तम्भ सं० P-1 से P 13 तक एक close figure बन रही है। जो कि इस कार्यालय के OSM के 1:50,000 (संस्करण 2012) के मानचित्र के लगभग अनुरुप है। स्तम्भ सं० P-7 की ground position की जानकारी वन प्रभाग एवं राजस्व विभाग को sure नहीं थी जिसके कारण स्तम्भ सं० P-7 की निर्देशांक tentative है।

*(ii) इस निदेशालय द्वारा सन 1979-80 में सर्वे की गई PT. सं० 530/7 मे ज्ञात होता है कि P-1 से P-13 तक की figure (आकृति) उपरोक्त P.T. section से match कर रही है तथा सं० A-1 से A-17 तक की आकृति इस PT section में नहीं दर्शायी गयी है। अर्थात **A-1 से A-17 तक का क्षेत्र PT Section के अनुसार वन क्षेत्र है** (प्रति संलग्न)। इस PT section के Forest boundary verification chart को सम्बन्धित राजस्व एवं वनाधिकारी द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित किया गया है (प्रति संलग्न)।*

*उपरोक्त के दृष्टिगत इस **निदेशालय का मत है कि दर्शाया गया A-1 से A-17 तक का क्षेत्र वन भूमि होना प्रतीत होता है।”***

English Translation

“1. For compliance the above orders, Directorate UKGD, Survey of India had called a meeting on 01-08-2024 through letter no. 1439/17-A-5 (L) dated 29-07-2024, The Forest Division, Nainital informed through letter no.-99/ Dehradun dated 01-08-2024 that due to heavy rains in Nainital, they are unable to participate in the meeting, hence again a meeting was called on 02-08-2024 (letter no. 1470/17-A-5(L) dated 01-08-2024) in which only Forest Division, Nainital participated and no representative of Revenue Department attended the meeting.

2. After discussions with Forest Division, Nainital and study of records, it was decided to survey the disputed site through GPS

observation. Also, we tried to know the reality of the situation by superimposing the map (Scale 1:15.00) provided by Forest Division, Nainital on OSM Sheet No. 530/7 of Survey of India.

3. In compliance with the letter No. 1212/1147-Project (General)/2070 dated 01-8-2024 of the Office of the Surveyor General of India, a team was formed under the leadership of Mohammad Fareed, Officer Surveyor for GPS survey of the disputed site and this team carried out the survey from 28-08-2024 to 02-09-2024. The report of the GPS survey is as follows-

(i) On plotting the coordinates obtained from GPS survey, it was found that a close figure is being formed from pillar number P-1 to P-13. Which is almost in line with the OSM map of this office at 1:50,000 (version 2012). The Forest Division and Revenue Department were not sure about the ground position of pillar number P-7, due to which the coordinates of pillar number P-7 are tentative.

(ii) In the PT No. 530/7 surveyed in 1979-80 by SoI, it is seen that the figures from P-1 to P-13 match the above PT section and the figures from A-1 to A-17 are not shown in this PT section. That is, the ***area from A-1 to A-17 falls in forest area*** *as per the PT Section (copy enclosed). The forest boundary verification chart of this PT section has been verified and signed by the concerned revenue and forest officer (copy enclosed).*

In view of the above, this ***Directorate is of the opinion that the area from A-1 to A-17 shown appears to be forest land."***

15. Learned counsel appearing State of Uttarakhand stated that now, in the light of report submitted by Survey of India, boundary dispute of land in question shall be finalized by passing necessary orders and issuing appropriate map and thereafter if it is found that any part of Khasra No. 424 is part of forest land and there is encroachment, appropriate action shall be taken in accordance with law.

16. Respondent 7 is present in person and stated that Khasra No. 424 in its entirety, is a revenue land and not part of forest, hence, it cannot be said that he has encroached upon forest land.

17. This issue does not arise to be adjudicated at this stage, since it involves title dispute of land therefore, it is open to aggrieved person to avail remedy in common law, as available, by filing suit for declaration in Civil Court.

18. So far as this Tribunal is concerned, Forest Conservation Act, 1980 is one of the enactment mentioned in Schedule I of NGT Act, 2010 and if there is any violation of provisions of such Act, the same has to be enforced by Tribunal.

19. In the circumstances, if there is any forest land which is being used for 'non-forest activity', without requisite permission from competent authority, such activity cannot be allowed to continue and direction can be issued by Tribunal for preventing such activities.

20. In the present case, State of Uttarakhand is yet to take a final decision in the matter with regard to Khasra No. 424, whether entire Khasra No. 424 or any part thereof falls within 'Reserved Forest' and whether there is any encroachment. Any order at this stage with regard to alleged encroachment and its removal will be premature.

21. We accordingly dispose of this OA directing State of Uttarakhand to take final decision in the matter, with regard to boundary dispute of Khasra No. 424, in the light of report of Survey of India and pass appropriate order in accordance with law expeditiously and in any case within two months. If it is found that entire or any part of Khasra No. 424 falls within 'reserved forest' area and there is any encroachment, appropriate action in accordance with law shall be taken for removal of such encroachment.

22. We also make it clear that this order shall not preclude respondent 7 from availing such remedy with regard to land dispute as available in law.

23. Compliance report shall be submitted by State of Uttarakhand by 15.12.2024 with Registrar General of this Tribunal, who, if finds any further order is required, shall place the matter before the Bench concerned.

24. O.A is accordingly disposed of.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

September 23, 2024
Original Application No. 709/2023
(IA No. 272/2024)
AB